



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55918

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7794 वर्ष 2026

विमला देवी

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: कृष्णा दत्त तिवारी, रणविजय चौबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

इसके साथ ही:

1. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4594 वर्ष 2026:

नाथू वर्मा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

न्यायालय संख्या - 67

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. राज्य द्वारा दायर प्रति-शपथ और आवेदक नत्थू वर्मा की ओर से दायर प्रत्युत्तर शपथपत्र को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. चूंकि दोनों जमानत याचिकाएं संबंधित हैं और एक ही एफआईआर से संबंधित हैं, इसलिए दोनों जमानत याचिकाओं का निपटारा एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण दत्त तिवारी और राज्य के विद्वान एजीए श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
4. दोनों जमानत याचिकाएं वाद अपराध संख्या 330/2025, धारा 85, 80(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस और धारा 3/4 डीपी एक्ट, पुलिस स्टेशन निचलौल, जिला महाराजगंज में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदकों की जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई हैं।
5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक मृतक के ससुराल वाले हैं और झूठे और सामान्य आरोपों के आधार पर उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।
6. इसके बाद उन्होंने कहा कि वास्तव में पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते रहते थे, क्योंकि मृतका हमेशा अपने मायके जाने की जिद करती थी और घटना वाले दिन भी ऐसा ही विवाद हुआ और इस बार उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु के बाद, उसके ससुराल वालों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि मृतका की मृत्यु फांसी के कारण हुई।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि हालांकि, इस मामले के अलावा, आवेदक नत्थू वर्मा, यानी मृतका के ससुर का भी आपराधिक इतिहास है, दो अन्य मामलों में, लेकिन दोनों मामले छोटे अपराधों से संबंधित हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले के आवेदक 10.12.2025 से जेल में हैं, यानी पिछले 3 महीनों से अधिक समय से।
8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की अर्जी का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तथ्यों पर आधारित तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और मामले का रिकॉर्ड देखा।
10. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक मृतक के ससुराल वाले हैं और उनके खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, मृतक की मृत्यु फांसी के कारण हुई है, और आवेदक नत्थू वर्मा का आपराधिक इतिहास स्पष्ट किया जा चुका है, और आवेदक विमला देवी एक महिला हैं, और वे पिछले 3 महीनों से अधिक समय से जेल में हैं, मेरी राय में, आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
11. तदनुसार, मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, दोनों जमानत याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।
12. आवेदक - **विमला देवी और नत्थू वर्मा** को उपरोक्त मामले में व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक जमानत राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

13. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदनों के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18 मार्च, 2026

शहरोज़

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”